



शरद कुमार यादव\*

## अंतरराष्ट्रीय व्यापार और पर्यावरणीय संपोषणीयता: व्यापार का हरितकरण

### प्रस्तावना

अंतरराष्ट्रीय व्यापार और पारिस्थितिक तंत्र के बीच का संबंध काफी जटिल एवं बहुआयामी है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार विभिन्न देशों के मध्य वस्तुओं, सेवाओं और पूंजी का प्रवाह है जो तुलनात्मक लाभ, बाजार के अवसरों और आर्थिक अन्योन्याश्रय द्वारा संचालित होता है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार न केवल वैश्विक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बल्कि यह विविध उत्पादों और प्रौद्योगिकियों को बाजारों तक पहुंच का मंच भी प्रदान करता है। वहीं पर्यावरणीय संपोषणीयता (सस्टेनेबिलिटी) प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण प्रबंधन की वकालत करता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आने वाली पीढ़ियों की संसाधन-क्षमता को खतरे में डाले बगैर वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति हो। इसके तहत पारिस्थितिकी तंत्र का सुरक्षा, संरक्षण और संवर्धन सम्मिलित हैं। दरअसल, वर्तमान वैश्वीकृत दुनिया में अंतरराष्ट्रीय व्यापार आर्थिक वृद्धि और विकास के लिए लाभदायक तो है, लेकिन ऐसी प्रगति के परिणामस्वरूप पारिस्थितिकी तंत्र को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिससे कई सवाल पैदा होते हैं। मसलन, आर्थिक मोर्चे पर हमारी जितनी सक्रियता बढ़ी है, क्या उसी अनुपात में पर्यावरणीय मोर्चे पर भी हम सक्रिय हुए हैं? दूसरा सवाल यह है कि क्या दुनिया आर्थिक लाभ बनाम पर्यावरणीय सुरक्षा के परस्पर विपरीत द्वन्द में तो नहीं फँस गया है? उपर्युक्त सवालों को ध्यान में रखते हुए, यह लेख अंतरराष्ट्रीय व्यापार और पर्यावरणीय संपोषणीयता के बीच जटिल संबंधों पर गहराई से चर्चा करता है तथा उन विभिन्न कारकों की भी छानबीन करता है जिसकी वजह से

पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुँचता है। इसके अतिरिक्त, यह उन संभावित रणनीतियों की भी चर्चा करता है जो इन प्रतिकूल प्रभावों को कम करने में मददगार साबित हो और टिकाऊ भविष्य के लिए व्यापार और पर्यावरण के मध्य संतुलन का मार्ग प्रशस्त कर सके।

### व्यापार बनाम पर्यावरण: विमर्शों के इर्द-गिर्द

व्यापार-पर्यावरण विमर्श आर्थिक विकास और पृथ्वी की सुरक्षा के बीच संतुलन खोजने के इर्द-गिर्द घूमती है, जिस पर दशकों से बहस चल रही है और इसमें विभिन्न दृष्टिकोण और हितधारक शामिल हैं। कुछ विद्वान ऐसा तर्क देते हैं कि व्यापार को बढ़ावा देने से प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन होता है, जिससे न केवल प्रदूषण बढ़ता है बल्कि पारिस्थितिक तंत्र का क्षरण भी होता है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार और पर्यावरणीय क्षति के बीच संबंध पर अध्ययन करते हुए, कई विद्वानों ने महत्वपूर्ण अध्ययन किए हैं। उदाहरण के लिए, एस्केलैंड और हैरिसन (2003), कोल (2004), टेलर (2004) और शेन तथा अन्य (2019) ने अपने अध्ययनों में पाया है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार का पर्यावरण प्रदूषण में प्रमुख योगदान है। व्यापार से जुड़ी गतिविधियाँ, मसलन उत्पादन, उपभोग और परिवहन इत्यादि प्रदूषण, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन में वृद्धि करती हैं। इसके अतिरिक्त, ली और अन्य (2018) द्वारा किए गए एक अध्ययन ने विशेष रूप से इस बात पर प्रकाश डाला है कि कैसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार व्यापक औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देता है, जिसके परिणामस्वरूप ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि और प्राकृतिक संसाधनों की कमी होती है।

\*सहायक प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान विभाग, शहीद भगत सिंह सांध्य महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय।

अहम बात यह है कि इस तरह की प्रक्रिया को नवउदारतावादी चिंतक अर्थशास्त्री साइमन कुजनेट्स द्वारा प्रतिपादित पर्यावरणीय वक्र की परिकल्पना के आधार पर उचित ठहराते हैं। कुजनेट्स ने तर्क दिया था कि आर्थिक विकास के शुरुआती चरणों में प्राकृतिक संसाधनों के अधिकतम दोहन से अपशिष्ट उत्पादों का ज़्यादा से ज़्यादा उत्सर्जन होता है। लेकिन जब कोई देश विकास की एक निश्चित अवस्था हासिल कर लेता है तो मैनुफैक्चरिंग में हुए प्रौद्योगिकीय विकास की वजह से पर्यावरणीय क्षय में गिरावट आने लगती है (टिसडेल, 2001)।

इस तरह के तर्क का समर्थन करने वाले अन्य विद्वान भी यह मानते हैं कि व्यापार पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं और नई तकनीकों को बढ़ावा देकर पर्यावरणीय गुणवत्ता को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। शिराज़ी और मानप (2005) तथा ह्ये तथा अन्य (2013) द्वारा किए गए अध्ययनों में दिखाया है कि जब कोई देश अंतरराष्ट्रीय व्यापार में शामिल होता है, तो उसकी राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। इस आय वृद्धि के परिणामस्वरूप, नागरिक पर्यावरण संरक्षण पर अधिक जोर देते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस धारणा के समर्थकों का तर्क है कि जैसे-जैसे कोई देश वाणिज्य के माध्यम से आर्थिक रूप से प्रगति करता है, वैसे-वैसे पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने वाले नियमों और कार्यप्रणालियों की आवश्यकता भी बढ़ती जाती है।

साथ ही इस विचार के समर्थक यह भी तर्क देते हैं कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है, बल्कि हरित प्रौद्योगिकियों में निवेश को भी प्रोत्साहित करता है। वैश्वीकरण विकसित देशों से पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों और प्रबंधन प्रणालियों के हस्तांतरण को सुगम बनाता है, जिससे वे विकासशील देशों तक पहुंच सकते हैं। प्रदूषण हेलो सिद्धांत बताता है कि कैसे वैश्वीकरण विकसित देशों से विकासशील देशों में स्वच्छ प्रौद्योगिकियों और संपोषणीय प्रथाओं के हस्तांतरण में सहायक होता है। यह हस्तांतरण प्रदूषण को कम करने और पर्यावरण के अनुकूल विकास को गति देने में मदद करता है, हालांकि यह गति धीमी होती है (झोउ और अन्य, 2018)।

उपर्युक्त विश्लेषणों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि विभिन्न विश्लेषकों ने इस संबंध को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा है। इस जटिल मुद्दे को बेहतर ढंग से समझने के लिए, व्यापार और पर्यावरण के व्यावहारिक निहितार्थों पर चर्चा करना महत्वपूर्ण है जो जमीनी स्तर पर विभिन्न रूपों में प्रकट होता है, जिस पर हम अगले भाग में चर्चा करेंगे।

### अंतरराष्ट्रीय व्यापार और पर्यावरणीय चुनौतियाँ

अंतरराष्ट्रीय व्यापार ने वैश्विक आर्थिक विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन इसके नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव को भी देखना महत्वपूर्ण है। एक अध्ययन से पता चलता है कि पिछले 30 वर्षों में कोई भी देश अपने नागरिकों की बुनियादी जरूरतें पूरी करने में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना सफल नहीं रहा है। विकसित देशों ने भी अपने संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया है। बढ़ते व्यापार, औद्योगिक उत्पादन और लंबी दूरी के परिवहन के कारण वायु प्रदूषण में वृद्धि हुई है, जिसके परिणामस्वरूप मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, दुनिया की करीब नब्बे फीसदी आबादी दूषित हवा में सांस लेने को मजबूर है। इस रिपोर्ट के अनुसार हर साल 42 लाख मौतों के लिए सीधे तौर पर आउटडोर एयर पोल्यूशन ही जिम्मेदार है। जिनमें से करीब 90 फीसदी मौतें गरीब और मध्यवर्गीय देशों में ही होती हैं। जबकि आउटडोर और इंडोर एयर पोल्यूशन से होने वाली मौतों के आंकड़ों को जोड़ दिया जाए तो इसके कारण हर साल करीब 88 लाख लोगों की मौत हो जाती है (डबल्यूएचओ, 2018)। जल प्रदूषण, जो औद्योगिक और कृषि अपशिष्टों से उत्पन्न होता है, जल स्रोतों को दूषित करता है और मानव जीवन के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है। वांग और अन्य (2024) द्वारा किया गया एक हालिया अध्ययन ने चिंताजनक आंकड़े पेश किए हैं: वर्ष 2050 तक, चार करोड़ वर्ग किलोमीटर से अधिक नदी घाटी क्षेत्र और तीन अरब अतिरिक्त लोग साफ पानी की कमी का सामना करेंगे। यह पहले के अनुमानों की तुलना में काफी अधिक है और यह दर्शाता है कि जलवायु परिवर्तन और अत्यधिक जल निकासी के कारण पानी की कमी की समस्या तेजी से बढ़ रही है (वांग और अन्य, 2024)।

अधिकतम व्यापार को बढ़ावा देने के लिए रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर बढ़ती निर्भरता मिट्टी की गुणवत्ता को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रही है, जिससे वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा हो रहा है। लगभग 92.4 करोड़ लोग (दुनिया की आबादी का 11.7%) भयंकर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं (यूनिसेफ, 2022)। जैव विविधता के क्षरण में व्यापार भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कृषि भूमि के विस्तार और शहरीकरण के कारण वन्य जीव आवास नष्ट हो रहे हैं, जिससे अनेक प्रजातियों के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। डबल्यूडबल्यूएफ की 'लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2020' के अनुसार, 1970 से 2016 तक स्तनधारियों, पक्षियों, मछलियों, पौधों और कीड़ों की संख्या में औसतन 68 फ़ीसदी की गिरावट आई है, जो पचास वर्ष से भी कम समय में दो-तिहाई से अधिक है (डबल्यूडबल्यूएफ, 2020)। वन्यजीव उत्पादों की अंतरराष्ट्रीय मांग कई प्रजातियों को विलुप्ति के कगार पर धकेल रही है। वस्तुओं की बढ़ती वैश्विक मांग वनों की कटाई और पर्यावरणीय क्षरण में योगदान दे रही है, जिसके परिणामस्वरूप उत्सर्जन में वृद्धि हो रही है। अनुमान है कि 29 फ़ीसदी से लेकर 39 फ़ीसदी वनों की कटाई अंतरराष्ट्रीय व्यापार से प्रेरित है (पेनड्रील और अन्य, 2019)।

आयातित और निर्यात किए गए वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और परिवहन से उत्पन्न ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है। अनुमानों के अनुसार, ये उत्सर्जन वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के बीस से तीस फ़ीसदी के बीच योगदान करते हैं (डबल्यूटीओ, 2021)। मल्टीनेशनल कंपनियों द्वारा प्रदूषणकारी उत्पादन की आउटसोर्सिंग भी एक चिंताजनक प्रवृत्ति है। ये कंपनियां अक्सर कमजोर पर्यावरणीय नियमों वाले देशों में अपने प्रदूषणकारी कारखानों को स्थापित करती हैं, जिसके परिणामस्वरूप स्थानीय पर्यावरणीय क्षरण और वैश्विक प्रदूषण में वृद्धि होती है (बेन-डेविड और अन्य, 2020)। इस प्रकार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार संसाधनों के अति-दोहन, प्रदूषण, जैव विविधता की हानि और जलवायु परिवर्तन के माध्यम से पर्यावरणीय स्थिरता को खतरे में डालता है।

## भारत की स्थिति: पर्यावरण और व्यापार में संतुलन

व्यापारिक हितों और पर्यावरण संबंधी चिंताओं के बीच चल रहा टकराव राष्ट्रों के लिए अनेक चुनौतियां प्रस्तुत करता है, भारत भी इसका अपवाद नहीं है। पिछले भाग में प्रस्तुत आंकड़े इस सत्य को और पुष्ट करते हैं तथा उन पर्यावरणीय चुनौतियों को दर्शाते हैं जिनका भारत को भी सामना करना पड़ रहा है। लेकिन, यह भी सच है कि भारत ने संपोषणीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए हैं, जो न केवल पर्यावरण की रक्षा करने में मदद करती हैं, बल्कि संसाधनों का कुशल उपयोग और समग्र आर्थिक विकास भी सुनिश्चित करती हैं।

ग्रीन तकनीकों के विकास, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन और जैविक खेती के संवर्धन के माध्यम से, देश ने पर्यावरणीय संपोषणीयता और आर्थिक वृद्धि को संतुलित करने के प्रयास किए हैं। उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय सौर मिशन और उजाला योजना ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा दे रहे हैं, जबकि राष्ट्रीय पवन ऊर्जा मिशन नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा दे रहा है। सिक्किम का पूर्ण जैविक राज्य बनना और स्वच्छ भारत अभियान की पहल भारत की इस दिशा में प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। पेरिस समझौते के प्रति भारत की प्रतिबद्धता कार्बन उत्सर्जन को कम करने और नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इन पहलों के माध्यम से, भारत न केवल अपने पर्यावरणीय दायित्वों को पूरा कर रहा है बल्कि वैश्विक स्तर पर टिकाऊ विकास के लिए एक उदाहरण भी प्रस्तुत कर रहा है।

भारत ने व्यापार से उत्पन्न पर्यावरणीय प्रभावों को नियंत्रित करने के लिए ठोस उपाय लागू किए हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986, जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत कठोर पर्यावरणीय मानकों को स्थापित किया गया है। सतत् आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन सर्टिफिकेशन और पर्यावरणीय लेखा-जोखा का पालन किया जा रहा है। नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार के लिए राष्ट्रीय सौर मिशन और राष्ट्रीय पवन ऊर्जा मिशन लागू किए गए हैं, जो कोयला आधारित ऊर्जा

उत्पादन पर निर्भरता को कम करते हैं। उजाला योजना के तहत 37 करोड़ से अधिक एलईडी बल्ब वितरित किए गए हैं, जिससे बिजली की खपत और CO<sub>2</sub> उत्सर्जन में कमी आई है। वही प्रारंभिक उत्सर्जन ट्रेडिंग प्रणाली के माध्यम से विभिन्न उद्योगों को अधिक ऊर्जा-कुशल बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।

भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा के विकास को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जो देश के ऊर्जा परिदृश्य को बदल रहे हैं। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना के तहत, एक मजबूत ट्रांसमिशन नेटवर्क का निर्माण किया जा रहा है जो नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों और उपभोक्ताओं को जोड़ता है, विशेषकर लद्दाख और गुजरात में स्थापित प्रमुख नवीकरणीय ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से। वित्तीय प्रोत्साहन जैसे उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन और पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र ने इस क्षेत्र में निवेश को आकर्षित किया है, जबकि सोलर रूफटॉप सब्सिडी और वित्तीय अनुदान ने घरेलू और व्यावसायिक स्तर पर सौर ऊर्जा की स्थापना को प्रोत्साहित किया है। इसके अलावा, नवीकरणीय ऊर्जा अनुसंधान और विकास के लिए विशेष बजट आवंटन और राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोगशाला के साथ वैज्ञानिक सहयोग ने सस्ती और कुशल ऊर्जा तकनीकों के विकास को संभव बनाया है। प्रौद्योगिकी का उपयोग करके वास्तविक समय में पर्यावरणीय निगरानी को सुदृढ़ किया गया है, जिसमें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ऑनलाइन प्रणालियाँ और राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक शामिल हैं। इसके अलावा, उत्सर्जन मानकों का कठोर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए ऑटोमोबाइल और थर्मल पावर प्लांट्स को उन्नत किया गया है।

भारत सर्कुलर इकॉनमी को अपनाकर व्यापार और पर्यावरण के बीच संतुलन स्थापित करने की दिशा में उल्लेखनीय कदम उठा रहा है। सर्कुलर इकॉनमी का मॉडल पारंपरिक लीनियर इकॉनमी (उपयोग और निपटान) के विपरीत, संसाधनों के पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण और पुनर्वास पर केंद्रित है। इस मॉडल का लक्ष्य है कि उत्पादों और सामग्रियों के मूल्य को जितना संभव हो सके, आर्थिक प्रणाली में

बनाए रखा जाए। स्वच्छ भारत मिशन और स्वच्छ भारत अभियान के तहत कचरा प्रबंधन और स्वच्छता को बढ़ावा दिया गया है, जिसमें कचरे को ऊर्जा में परिवर्तित करने की परियोजनाएँ शामिल हैं। प्लास्टिक और खतरनाक कचरे के प्रबंधन के लिए प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम, 2016 और ई-कचरा प्रबंधन नियम, 2016 के तहत विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी और सुरक्षित पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित किया गया है। ये सभी पहलें भारत को एक टिकाऊ विकास मॉडल की ओर अग्रसर करती हैं, जो पर्यावरणीय संरक्षण और आर्थिक विकास दोनों को संतुलित करने में कारागार साबित होगी।

### आगे की राह

पिछले चार दशकों में पर्यावरणीय मुद्दों का महत्व विभिन्न मोर्चों पर बढ़ा है। साठ के दशक में, पर्यावरण के प्रति सार्वजनिक चिंता की पहली बड़ी लहर मुख्य रूप से उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में औद्योगिक प्रदूषण की समस्याओं पर केंद्रित थी। सत्तर के दशक के उत्तरार्ध में, व्यावसायिक मूल्यांकन में पर्यावरणीय मुद्दों को शामिल करना शुरू हुआ। अस्सी के दशक में उथल-पुथल भरे दौर में, सीमा पार पर्यावरण संबंधी मुद्दों को महत्वपूर्ण व्यापार वार्ताओं में शामिल किया जाने लगा और नब्बे के दशक के आते-आते यह स्पष्ट हो गया कि अलग-अलग पर्यावरण संबंधी नियमों में राष्ट्रों और क्षेत्रों की प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित करने की क्षमता है। परिणामस्वरूप, प्रभावी पर्यावरण विनियमन और उनकी तुलनात्मकता का महत्व बढ़ने लगा। इस दौरान, पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में बढ़ती चिंताओं ने वैश्विक ध्यान आकर्षित करना शुरू कर दिया (जयदेवप्पा और छत्रे, 2000)।

दरअसल, व्यापार और पर्यावरण के बीच संबंध जटिल और गतिशील है, जो निरंतर विकसित हो रहा है। पिछले कुछ दशकों में हुई प्रगति ने टिकाऊ भविष्य के लिए व्यापार की भूमिका के बारे में नए दृष्टिकोण अपनाने को प्रेरित किया है। ध्यान रहे, व्यापार विभिन्न स्तरों पर पर्यावरण को प्रभावित करता है, जिससे विभिन्न चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए, व्यापार और पर्यावरण गुणवत्ता के बीच के संबंध को समझना आवश्यक

है। व्यापार और पर्यावरण गुणवत्ता के बीच संबंध की जांच तीन अलग-अलग श्रेणियों में की जाती है, जो उत्पादन और उपभोग से उत्पन्न होने वाले पर्यावरणीय मुद्दों द्वारा निर्धारित की जाती हैं। पहली श्रेणी स्थानीय समस्याओं पर केंद्रित है जो एक ही देश में होती हैं, जैसे वायु और जल प्रदूषण, जिन्हें स्थानीय स्तर पर संबोधित करने की आवश्यकता होती है। दूसरी श्रेणी में अंतर-देशीय मुद्दे शामिल हैं जो तब उत्पन्न होते हैं जब कई देश नदियों या वायुमंडल जैसे साझा संसाधन के प्रदूषण में योगदान करते हैं, जिसके समाधान के लिए सहयोग की आवश्यकता होती है। अंत में, ओजोन परत की कमी जैसी वैश्विक समस्याएं पूरी दुनिया को प्रभावित करती हैं और उन्हें कम करने के लिए पर्याप्त अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता होती है (जयदेवप्पा एवं छत्रे, 2000)। इन तीन श्रेणियों के बीच मुख्य अंतर यह है कि पहली श्रेणी व्यापार और पर्यावरण को वस्तुओं और सेवाओं के आदान-प्रदान से जोड़ती है, जबकि अन्य दो श्रेणियां सीमा पार प्रदूषण से जुड़ी हैं। हालांकि, ऐसे उदाहरण हो सकते हैं जहाँ ये श्रेणियाँ आपस में जुड़ी हुई हों। यह समझना ज़रूरी है कि ये श्रेणियाँ पूरी तरह से अलग नहीं हैं और कुछ स्थितियों में एक दूसरे से जुड़ सकती हैं। उदाहरण के लिए, जबकि जलवायु परिवर्तन एक विश्वव्यापी मुद्दा है, इसके प्रभाव स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अनुभव किए जा सकते हैं (जयदेवप्पा एवं छत्रे, 2000)।

ऐसे में अंतरराष्ट्रीय व्यापार के पर्यावरणीय नकारात्मक प्रभावों को कम करने हेतु बहुस्तरीय और समन्वित रणनीतियों की आवश्यकता है। इनमें प्रमुख नीतियों में पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहित करने वाली व्यापारिक नीतियाँ सम्मिलित हैं, जैसे पर्यावरणीय शुल्क और ईको-लेबलिंग। पर्यावरणीय शुल्क, जैसे कार्बन टैक्स, उच्च प्रदूषण करने वाले उत्पादों पर अधिक कर लगाते हैं, जिससे उनकी खपत कम होती है। ईको-लेबलिंग उपभोक्ताओं को पर्यावरण-अनुकूल उत्पादों की पहचान करने में मदद करती है, जिससे कंपनियों को हरित उत्पादन विधियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है।

अंतरराष्ट्रीय पर्यावरणीय समझौते और नियम, जैसे पेरिस समझौता, क्योटो प्रोटोकॉल, वियना सम्मेलन और जैव

विविधता पर कन्वेंशन, देशों को एक साथ काम करने और कानूनी रूप से बाध्यकारी लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित करते हैं। जो इन समझौतों का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण जैसे वैश्विक मुद्दों का समाधान करना है। ये समझौते देशों को ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ तरीके से विकास करने के लिए प्रेरित करते हैं।

अंतरराष्ट्रीय संगठनों, जैसे विश्व व्यापार संगठन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। विश्व व्यापार संगठन व्यापार और पर्यावरणीय नीतियों के बीच तालमेल स्थापित करने के लिए कार्य करता है, जबकि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों पर अनुसंधान और नीति विकास में सहायता करता है। ये संगठन टिकाऊ व्यापार प्रथाओं और पर्यावरणीय मानकों के लिए वैश्विक सहयोग और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और हरित आपूर्ति श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कंपनियां अपने उत्पादन और वितरण प्रक्रियाओं को पर्यावरण के अनुकूल बनाकर ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम कर सकती हैं और कचरे को रीसायकल कर सकती हैं। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमों के तहत, कंपनियां पर्यावरणीय परियोजनाओं में निवेश कर सकती हैं और स्थायी विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में योगदान दे सकती हैं।

जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में, व्यापार से जुड़े परिवहन उत्सर्जन में कमी को प्राथमिकता देना बहुत ज़रूरी है। इस लक्ष्य को उन्नत परिवहन तकनीकों के क्रियान्वयन, टिकाऊ ईंधन के उपयोग और परिवहन नेटवर्क के विस्तार के ज़रिए हासिल किया जा सकता है। इसके अलावा, प्रौद्योगिकी, विशेषज्ञता और वित्तीय सहायता का आदान-प्रदान महत्वपूर्ण है। पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकियों के एकीकरण को सुगम बनाना, संधारणीय तरीकों पर ज्ञान प्रदान करना और संधारणीय व्यावसायिक प्रथाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना इस प्रयास में प्रमुख तत्व हैं। छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों, विशेष रूप से उच्च कार्बन-उत्सर्जन वाले क्षेत्रों में, वैश्विक मानकों और

पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं के अनुरूप होने में सहायता करना अनिवार्य है। इन उपायों के कार्यान्वयन के माध्यम से, व्यवसाय वैश्विक बाजार में अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रख सकते हैं और साथ ही पर्यावरण पर अंतरराष्ट्रीय व्यापार के हानिकारक प्रभावों को भी कम कर सकते हैं।

## निष्कर्ष

अंतरराष्ट्रीय व्यापार वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, लेकिन पर्यावरण पर इसके प्रभावों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। संपोषणीय व्यापार, आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर, एक स्थायी भविष्य का मार्ग प्रशस्त करता है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग महत्वपूर्ण है। विभिन्न राष्ट्रों, व्यावसायिक समूहों, नागरिक समाज और अंतरराष्ट्रीय संगठनों को मिलकर काम करने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि व्यापार पर्यावरण के अनुकूल और न्यायसंगत हो। यह चुनौतीपूर्ण है, लेकिन यह सब की सामूहिक जिम्मेदारी भी है। आज उठाया हुआ कदम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर कल साबित होगा। इसलिए, मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, विशेष रूप से कम संसाधनों वाले देशों को, हरित अर्थव्यवस्था में बदलाव लाने और अपने डीकार्बोनाइजेशन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विशेषज्ञता, प्रौद्योगिकी और वित्तपोषण तक पहुंच प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। संबंधित हितधारक इस अंतर को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं और देशों को व्यापार के पर्यावरण पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों को कम करने और सकारात्मक प्रभावों को अधिकतम करने में सहायता प्रदान कर सकते हैं।

## संदर्भ

शिराजी, एन. एस., एंड मणप, टी. ए. ए. (2005). एक्सपोर्ट-लेड ग्रोथ हाइपोथेसिस: फ़र्दर इकोनोमेट्रिक एविडेंस फ्रॉम साउथ एशिया. डेवलपिंग इकॉनमीज़, 43(4), 472-488.

एस्केलैंड, जी. एस., & हैरिसन, ए. ई. (2003). मूविंग टू ग्रीनर पासर्स? मल्टीनेशनल्स एंड द पॉल्यूशन हेवन हाइपोथेसिस. 1016/S0304-3878(02)00084-6

कोल, एम. ए. (2004). ट्रेड, द पॉल्यूशन हेवन हाइपोथेसिस एंड द एनवायरनमेंटल कुज़नेट्स कर्व: एग्जामिनिंग द लिंकिंग. इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स., 48(1), 71-81.

टेलर, एम. एस. (2004). अनबंडलिंग द पॉल्यूशन हेवन हाइपोथेसिस. एडवांस इन इकोनॉमिक एनालिसिस एंड पॉलिसी., 3(2), 1-28.

शेन, जे., वांग, एस., लियू, डब्ल्यू., & चू, जे. (2019). डज़ माइग्रेशन ऑफ़ पोल्यूशन-इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ इम्पैक्ट एनवायरनमेंटल एफिसिएंसी? एविडेंस सपोर्टिंग "पोल्यूशन हेवन हाइपोथिसिस". जर्नल ऑफ़ एनवायरनमेंटल मैनेजमेंट, 242, 142-152.

झोउ, वाय., फू, जे., कोंग, वाय., & वू, आर. (2018). हाउ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन्पलूएंससे कार्बन इमिशन, बेसड ऑन द एम्पिरिकल एनालिसिस ऑफ़ चाइनीज़ अर्बन डेटा. सस्टेनेबिलिटी., 10(7), 2163.

कोपलैंड, बी. आर., शापिरो, जे. एस., & टेलर, एम. एस. (2021). ग्लोबलाइजेशन एंड द एनवायरनमेंट. एनबीईआर वर्किंग पेपर 28797.

ली, जे., झांग, वाय., हू, वाय., ताओ, एक्स., जियांग, डब्ल्यू., & क्यू, एल. (2018). डिवेलपिंग मार्केट ऑर डेवलपिंग मार्केट? ए पर्सपेक्टिव ऑफ़ इंस्टिट्यूशनल थ्योरी ऑन मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेज' डाइवर्सिफिकेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन. बिजनेस स्ट्रैटेजी एंड द एनवायरनमेंट, 27(7), 858-871.

टिस्डेल, सी. (2001). ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबिलिटी: एनवायरनमेंटल कुज़नेट्स कर्व एंड द डब्ल्यूटीओ. इकोलॉजिकल इकॉनॉमिक्स, 39(2), 185-196.

सोरोच-डेल-रे, वाय., पिएद्रा- मुनोज़, एल., & गाल्डेआनो-गॉज, ई. (2023). इंटररिलेशनशिप बिट्वीन इंटरनेशनल

ट्रेड एंड एनवायरनमेंटल परफॉर्मेंस: थ्योरिटिकल अप्रोचेज एंड इंडिकेटर्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. बिजनेस स्ट्रैटेजी एंड द एनवायरनमेंट, 32(6), 2789-2805.

वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन. (2018, अक्टूबर 22). 9 आउट ऑफ 10 पीपल वर्ल्डवाइड ब्रीथ पोल्यूटेड एयर, बट मोर कंट्रीज़ आर टेकिंग एक्शन [प्रेस रिलीज़].

वांग, एम., बोडिस्की, बी. एल., रिजनेवेल्ड, आर., बायर, एफ., बाक, एम. पी., बटूल, एम., & स्ट्रोकल, एम. (2024). ए ट्रिपल इंक्रिज़ इन ग्लोबल रिवर बेसिन्स विथ वाटर स्कार्सिटी ड्यू टू फ्यूचर पॉल्यूशन. नेचर कम्युनिकेशंस, 15(1), 880.

यूनिसेफ. (2022). द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड (SOFI) रिपोर्ट-2022.

डब्ल्यूडब्ल्यूएफ. (2020). लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2020:

बेंडिंग द कर्व ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस. इन आर. ई. ए. आल्मोंड, एम. गूटेन, & टी. पीटर्सन (स.), डब्ल्यूडब्ल्यूएफ, ग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड.

पेंड्रिल, एफ., पर्सन, यू. एम., गोडार, जे., कास्टनर, टी., मोरान, डी., शिमट, एस., & वुड, आर. (2019). एग्रीकल्चरल एंड फॉरेस्ट्री ट्रेड ट्राइव्स लैर्ज शेयर ऑफ ट्राॅपिकल डेफॉरैस्टेशन इमिशनस. ग्लोबल एनवायरनमेंटल चेंज, 56, 1-10.

वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइजेशन. (2021). ट्रेड एंड क्लाइमेट चेंज – इन्फॉर्मेशन ब्रीफ न. 4.

बेन-डेविड, आई., जांग, वाय., क्लेमेयर, एस., & वीज, एम. (2020). एक्सपोर्टिंग पॉल्यूशन: व्हेयर डू मल्टीनेशनल फर्मर्स रिलीज़ सीओ<sub>2</sub>.



### IIBF organised Banking Conclaves in collaboration with UNEP FI and GIZ

IIBF organised a Banking Conclaves on “Sustainable Finance and Responsible Banking” in collaboration with UNEP FI and GIZ in August 2024 in New Delhi, Kolkata and Chennai. The objective of Banking Conclaves were to delve deeper into the roles and responsibilities of Board members and Senior Management of the Financial Institutions, in promoting climate awareness and disclosures in Banks & FIs, thereby, advancing India’s climate transition. The event was attended by top dignitaries and Senior professionals from Banking & Financial Institutions and was appreciated by the attendees.